GEO IAS
It's about quality

2 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | PIB | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 2 July 2024

Important News Articles

1. CEPA समीक्षा: भारत चाहता है कि दक्षिण कोरिया कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम करे- द हिंदू
2. जनगणना के लिए सीमा तय करने की समयसीमा पर सरकार अनिर्णीत - द हिंदू
3. RBI और आसियान इंस्टेंट खुदरा भुगतान हेतु मंच का निर्माण करेंगे - द हिंदू
4. तालिबान पहली बार दोहा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुआ-द प्रिंट
5. छत्तीसगढ़ में मक्का और सोयाबीन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त संभावना : शिवराज सिंह चौहान - पीआईबी
6. कुनो में चीतलों की संख्या में कमी, अतिरिक्त चीतों को अन्य जगह स्थानांतरित करने की योजना-इंडियन एक्सप्रेस

Editorials, Gists and Explainers

7. अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू किया - द हिंदू
8. भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में 25M से अधिक नौकरियों के सृजन की आवश्यकता- द हिंदू
9. शहरी विस्तार से दिल्ली में बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ रहा है- इंडियन एक्सप्रेस
10. मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण - इंडियन एक्सप्रेस

Quick Look

1. प्रोजेक्ट 75I
2. सी-डैक
3. व्यायाम मैत्री
4. मार्स ओडिसी
5. प्रोजेक्ट नेक्सस

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. CEPA समीक्षा: भारत चाहता है कि दक्षिण कोरिया कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम करे- द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्रीलिम्स टेकअवे
- CEPA

समाचार:
- भारत चाहता है कि दक्षिण कोरिया कई वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त कर दे, जैसे कि मांस, दूध, फल, मछली, पत्थर, धागा और पेट्रोलियम उत्पाद, जिन्हें लगभग डेढ़ दशक पहले हस्ताक्षरित भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) में भारी कटौती से छूट दी गई थी या संरक्षित किया गया था।
- दोनों देश CEPA को उन्नत करने के लिए चल रही वार्ता में टैरिफ कटौती के लिए अनुरोध सूची पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार घाटे को कम करना भारत के एजेंडे में शीर्ष पर है।
- "भारतीय उद्योग के हितधारकों को मसौदा अनुरोध सूची प्रदान की गई है और उनसे और अधिक वस्तुओं का सुझाव देने के लिए कहा गया है जिन पर टैरिफ कटौती की मांग की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो हटाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। भारत-कोरिया CEPA उन्नयन बैठक का अगला दौर है।
- CEPA पर अगस्त 2009 में हस्ताक्षर किये गये तथा जनवरी 2010 में इसे क्रियान्वित किया गया।
  - इसमें वस्तुओं के व्यापार, निवेश, सेवाओं तथा साझा हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को शामिल किया गया है।
  - जबकि भारत ने दक्षिण कोरिया से आयातित 83.8% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उन्मूलन या रियायत की पेशकश की, वहीं दक्षिण कोरिया ने 93.2% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उन्मूलन या रियायत की पेशकश की है।

व्यापार घाटा
- दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार घाटे को कम करना भारत के वार्ता एजेंडे में शीर्ष मुद्दों में से एक है।
- वर्ष 2023-24 में, दक्षिण कोरिया से भारत का आयात 21.13 बिलियन डॉलर था जबकि निर्यात 6.41 बिलियन डॉलर था।
- शोध संस्था ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के विश्लेषण के अनुसार, CEPA (2007-09) से पहले भारत से दक्षिण कोरिया को औसत निर्यात 3.4 बिलियन डॉलर का था, जबकि औसत आयात 7.3 बिलियन डॉलर था, जिसके कारण औसत व्यापार घाटा 4 बिलियन डॉलर था।
- CEPA (2022-24) के बाद, औसत निर्यात बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर हो गया, और आयात बढ़कर 19.9 बिलियन डॉलर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप औसत व्यापार घाटा 12.8 बिलियन डॉलर हो गया।
- GTRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, "इससे CEPA-पूर्व अवधि से लेकर CEPA-पश्चात अवधि तक व्यापार घाटे में 7.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि का संकेत मिलता है, जो 220% की वृद्धि को दर्शाता है।"

2. जनगणना के लिए सीमा तय करने की समयसीमा पर सरकार अनिर्णीत - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जनगणना

समाचार:
- जनगणना कार्य के लिए प्रशासनिक सीमाएं निर्धारित करने की समय सीमा हाल ही में समाप्त हो गई, लेकिन नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

मुख्य बिंदु
- इस अस्पष्टता का सीधा असर 2011 में आयोजित जनगणना की तारीखों पर पड़ा है।
- दिसंबर 2020 से अब तक समय सीमा नौ बार बढ़ाई जा चुकी है।
- 30 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक सीमाओं को 30 जून, 2024 तक स्थिर रखने की अवधि बढ़ा दी गई, जिससे दशकीय जनगणना का कार्य प्रभावी रूप से कम से कम 1 अक्टूबर तक टल गया, क्योंकि इस कार्य के लिए गणनाकर्ताओं को तैयार करने में आमतौर पर तीन महीने का समय लगता है।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

- पिछले वर्ष संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण अधिनियम, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, का कार्यान्वयन जनगणना पर निर्भर है।

3. RBI और आसियान इंस्टेंट खुदरा भुगतान हेतु मंच का निर्माण करेंगे - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेक्सस
- आसियान

समाचार:
- भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों ने तत्काल सीमापार खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:
- इस प्लेटफॉर्म के वर्ष 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है।
- RBI ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को आपस में जोड़कर इंस्टेंट क्रॉस-बॉर्डर खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
- नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के FPS को जोड़ना है; तथा भारत, जो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।
- इस आशय के एक समझौते पर BIS और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- इंडोनेशिया, जो प्रारंभिक चरण से ही इसमें शामिल रहा है, विशेष पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल बना हुआ है।
- एक बार कार्यात्मक हो जाने पर, नेक्सस खुदरा सीमापार भुगतान को कुशल, तीव्र और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक भारत के FPS एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को सीमापार व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) भुगतान के लिए उनके संबंधित FPS के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है।
- जबकि भारत और उसके साझेदार देश तीव्र भुगतान प्रणालियों की ऐसी द्विपक्षीय कनेक्टिविटी के माध्यम से लाभ उठाते रहेंगे, बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करेगा।

4. तालिबान पहली बार दोहा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुआ-द प्रिंट

प्रासंगिकता: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- तालिबान

समाचार:
- तालिबान पहली बार कतर के दोहा में संयुक्त राष्ट्र (UN) के नेतृत्व वाली बैठक में भाग ले रहा है, जो रविवार को शुरू हुई, जिससे दुनिया भर में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है।

मुख्य बिंदु
- दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ
  - तालिबान सरकार के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस दौरान भारत ने दोहा बैठक में तालिबान के रुख का समर्थन किया और बदले में अफगानिस्तान को भारत की सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया।
- युद्धग्रस्त देश की अर्थव्यवस्था और पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आयोजित बैठक में प्रमुखता से चर्चा हुई, जहां नशीली दवाओं के खतरे और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
- तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफीम की खेती पर शासन के प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के संदर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों के अधीन तालिबान आर्थिक रूप से कमजोर बना हुआ है, तथा अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के सभी विदेशी रिज़र्व हैं।
- हालाँकि, कजाकिस्तान जैसे उसके कुछ पड़ोसी देशों ने तालिबान को अपने प्रतिबंधित समूहों की सूची से हटा दिया है।
- रूसी विदेश मंत्रालय कथित तौर पर इस पर विचार कर रहा है। इस बीच, चीन इस फरवरी में तालिबान शासन द्वारा नियुक्त राजदूत को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया।

सामान्य अध्ययन III

5. छत्तीसगढ़ में मक्का और सोयाबीन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त संभावना : शिवराज सिंह चौहान - पीआईबी

प्रासंगिकता: प्रमुख फसलें - देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न, - विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियाँ; कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन तथा मुद्दे और संबंधित बाधाएँ; किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- तिलहन
- दालें

समाचार:
- देश में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य से राज्यवार चर्चा शुरू की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री ने कृषि भवन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की गई है ।

मुख्य बिंदु:
- चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी आदि को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि एवं कृषक कल्याण से जुड़े कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
- केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मंत्री के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दलहन, तिलहन, बागवानी, नमो ड्रोन दीदी, ऑयल पाम मिशन सहित कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की है।
- उन्होंने दालों और तिलहनों को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति का भी उल्लेख किया।
- छत्तीसगढ़ में मक्का और सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में खाद, बीज आदि की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

6. कुनो में चीतलों की संख्या में कमी, अतिरिक्त चीतों को अन्य जगह स्थानांतरित करने की योजना-इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य

समाचार:
- प्रोजेक्ट चीता के अधिकारी सैद्धांतिक रूप से निर्णय पर पहुंच गए हैं कि मानसून के बाद कुनो राष्ट्रीय उद्यान से अतिरिक्त चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु
- वर्तमान में कुनो में 26 चीते हैं, जिनमें 13 शावक और उप-वयस्क शामिल हैं।
- यह कुनो की चीता वहन क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के बाद है - जिसे परियोजना कार्य योजना में 21 आंका गया है
  - कुनो के प्रमुख चीता शिकार आधार, चीतल आबादी में 2022 से 25 प्रतिशत से अधिक की चौंका देने वाली हानि के कारण यह आवश्यक हो गया है।
- एक वर्ष के भीतर अनुमानित 2,250 चीतलों की हानि ने परियोजना टीम को उलझन में डाल दिया है, क्योंकि उस अवधि के दौरान बाड़ों के बाहर जंगल में शिकार करने वाले सात चीते केवल लगभग 50 चीतलों का ही शिकार कर पाए।
- विडंबना यह है कि, तेंदुए राज्य के शिकार-समृद्ध जंगलों से लाए गए चीतलों को खाने के लिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 60 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में घुसकर चीतों के शिकार के लिए प्रजनन के प्रयासों को भी विफल कर रहे हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार कुनो में घटते स्टॉक की पूर्ति के लिए 1,500 चीतल लाने की प्रक्रिया में है और गांधी सागर में एक और चीतल भेजने की योजना बना रही है।
  - परियोजना प्राधिकारियों ने तेंदुए के शिकार को कम करने की रणनीति के बिना शिकार के अन्य आवासों को सूखाने की सीमाओं को स्वीकार किया है।
- इसलिए चीता परियोजना संचालन समिति, तेंदुए की गतिविधियों को कम करने और शिकार आधार पर दबाव को कम करने के लिए कुनो मिश्रण में एक बड़ी बिल्ली को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

7. अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां।
प्रसंग:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वें वित्त आयोग (FC) ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो मुख्य रूप से समेकित निधि के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से स्थानीय निकायों को संघीय प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है।
- इन संशोधनों द्वारा उप-धारा 280 (3) ((bb) और (c) प्रस्तुत की गई, जो वित्त आयोग को पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायता देने के लिए राज्य समेकित निधियों को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार देती है।

शहरों का योगदान

- 80 के दशक के मध्य में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने शहरों को "विकास के इंजन" के रूप में वर्णित किया था।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान लगभग 66% तथा कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% है।
- इस प्रकार, शहर देश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानिक क्षेत्र हैं।
- हालाँकि, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

शहर की वित्तीय सेहत का अवलोकन

- 11वें वित्त आयोग के बाद से पांच आयोगों के प्रयासों के बावजूद, शहरों को वित्तीय हस्तांतरण अपर्याप्त बना हुआ है।
- नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति खराब है, जिससे शहर की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है।
- उचित वित्तीय कार्रवाई के बिना तीव्र शहरीकरण से विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को अंतर-सरकारी हस्तांतरण (IGT) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5% है, जो अन्य विकासशील देशों के 2-5% से काफी कम है।
- यद्यपि IGTs, ULBs के कुल राजस्व का लगभग 40% बनाते हैं, फिर भी उनकी पूर्वानुमानितता, कमजोर समूहों के लिए निर्धारण, तथा क्षैतिज इक्विटी के संबंध में समस्याएं बनी हुई हैं।

कराधान प्रणाली

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से शहरी स्थानीय निकायों का कर राजस्व (संपत्ति कर को छोड़कर) वर्ष 2012-13 में लगभग 23% से घटकर वर्ष 2017-18 में लगभग 9% रह गया है।
- राज्यों से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले IGT बहुत कम हैं, राज्य वित्त आयोगों ने वर्ष 2018-19 में राज्यों के स्वयं के राजस्व का केवल 7% ही अनुशंसित किया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में IGT की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है।
- 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के उद्देश्य के बावजूद, पिछले तीन दशकों में प्रगति कम रही है।
- 13वें वित्त आयोग ने पाया कि "समानांतर एजेंसियां और निकाय स्थानीय सरकारों को वित्तीय और परिचालन दोनों दृष्टि से कमजोर बना रहे हैं।"
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे कार्यक्रम इस मुद्दे को बढ़ाते हैं तथा संघीय ढांचे को विकृत करते हैं।

आगे की राह

- वर्ष 2021 की जनगणना के अभाव में, साक्ष्य-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण के लिए वर्ष 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता अपर्याप्त है।
- इस प्रकार, 15वें वित्त आयोग के नौ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इनमें से सभी पर नहीं, बल्कि राज्य के GST के अनुरूप संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि; खातों का रखरखाव; प्रदूषण को कम करने के लिए संसाधन आवंटन; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आदि पर ध्यान देने के संदर्भ पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 16वें वित्त आयोग को भारत की शहरीकरण गतिशीलता पर विचार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में IGT कम से कम दोगुनी हो।

8. भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में 25M से अधिक नौकरियों के सृजन की आवश्यकता- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग:

- भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में 25 मिलियन से अधिक नौकरियों के सृजन की आवश्यकता है ताकि देश में वर्तमान में बेरोजगार सभी लोगों को रोजगार मिल सके।
- नरेन्द्र मोदी सरकार ने दावा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष 8% की प्रभावशाली गति से बढ़ी।
- लेकिन यदि यह दावा सही भी है, तो भी भारत में वर्तमान बेरोजगारी को देखते हुए, इससे पर्याप्त संख्या में उपयुक्त नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं।
- नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2021 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023 में 3.1% हो सकती है, लेकिन यह 8% की तीव्र GDP विकास दर के अनुरूप नहीं है।

असमानता का बढ़ाना

- पिछले दो दशकों में अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। इसके अलावा, पिछले एक दशक में, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि धन असमानता में तेज़ वृद्धि हुई है।
- भारत की लगभग 1% आबादी के पास अब देश की 40% संपत्ति है। यह किसी भी लोकतांत्रिक आबादी और राज्य के लिए भयानक है, न कि राष्ट्र की स्थिरता के लिए।
- इसे ही अर्थव्यवस्था में ग्राफिक रूप से "K-आकार" असमानता कहा जाता है, अर्थात, कुछ लोगों के लिए उपभोग/आय बढ़ रही है, जबकि कम संपन्न आबादी के बड़े हिस्से के लिए यह घट रही है, अर्थात, यह K-वार घट रही है।
- सार्वजनिक सभाओं में प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के पिछले नौ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है (पूंजीगत व्यय में भारी निवेश करके)
- सरकारी अर्थशास्त्रियों का भी दावा है कि मोदी सरकार ने सतत और तेज़ आर्थिक विकास स्थापित करने में सफलता पाई है, जिससे लोग खुश हैं। यह अगले तीन सालों में देखने वाली बात होगी।
- वास्तव में, चुनावी नतीजों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे सरकारी विशेषज्ञों ने समाचार मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया था - कि भारत "दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है।"

विकास में गिरावट की संभावना

- मोदी सरकार अक्सर दावा करती है कि वर्ष 2023-24 की 8.2% की GDP वृद्धि वर्ष 2022-23 की 7% की मजबूत वृद्धि के ऊपर आई है। इसकी गणना कैसे की गई, इसका खुलासा नहीं किया गया है।
- पिछले दो वर्षों में भारत की वृद्धि को सरकार के विशाल पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए काफी बड़े बजट घाटे के माध्यम से बढ़ावा मिला है।
- इसलिए, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई 8.2% की वृद्धि एक क्षणिक झलक प्रतीत होती है। यह संदिग्ध है कि क्या इसे वर्ष 2024-25 में बनाए रखा जा सकता है। वास्तव में, जो लोग गंभीर मात्रात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि विकास में और गिरावट आएगी।

नई रणनीति की आवश्यकता

- पिछले दशक के दौरान, इस सरकार के अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए अक्सर "अगली पीढ़ी के सुधारों" का आह्वान किया है।
- इसके अलावा, कृषि में 92% नौकरियाँ असंगठित क्षेत्र में हैं। उद्योग और सेवाओं में, सृजित नौकरियों में से 73% छोटे और मध्यम-अनौपचारिक वर्गों में हैं। सरकारी और औपचारिक निजी क्षेत्र में नौकरियों का हिस्सा मात्र 27% है। इस प्रकार, भारत को अब एक नई दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता है एक कठिन काम क्योंकि भाजपा के पास संसद में एकजुट बहुमत नहीं है और उसके पास संबंधित मंत्रियों से खुलकर बात करने के लिए कोई अर्थशास्त्री नहीं है।

9. शहरी विस्तार से दिल्ली में बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ रहा है- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
समाचार:

- अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया गया शहरी विस्तार दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार शहरी बाढ़ का मुख्य कारण है।

मुख्य बिंदु

- जल-जमाव के कारण लम्बे समय तक बिजली गुल रही, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और जान-माल का नुकसान हुआ, तथा कम से कम 11 लोगों की मौत संरचनाओं के ढहने और बिजली के झटके लगने के कारण हुई।
- नगर निगम अधिकारियों द्वारा नालों की अपर्याप्त सफाई जैसे कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन मूल रूप से दिल्ली एक अधिक बुनियादी समस्या से ग्रस्त है।

तेजी से बढ़ता शहर

- दिल्ली दुनिया के सबसे तेज़ शहरी विस्तार में से एक से गुज़र रही है। नासा की अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी के डेटा के अनुसार, वर्ष 1991 से वर्ष 2011 तक दिल्ली का भौगोलिक आकार लगभग दोगुना हो गया है।
- संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2018 में विश्व के शहरों की डेटा पुस्तिका के अनुसार,वर्ष 2030 तक दिल्ली, टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 39 मिलियन होगी, जो वर्ष 2000 की जनसंख्या से लगभग ढाई गुना अधिक है।

हर जगह कंक्रीट

- वास्तुकार और शहरी डिजाइनर केटी रविंद्रन ने बताया, "भूमि की ढलान रिज से नदी तक है यह लगभग 100 मीटर की खाई है।"
- दिल्ली के बाढ़ के मैदानों में निर्माण कार्य वर्ष 1900 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब अंग्रेजों ने नदी के किनारे रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया था।
- इस कंक्रीटीकरण के कारण वर्षा जल को मिट्टी में रिसने के लिए बहुत कम जगह बचती है, जिससे बाढ़ आ जाती है।

कोई 'जल मास्टरप्लान' नहीं

- बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करने वाले जल निकायों को भी व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में लगभग 1,000 जल निकाय हैं।

10. मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव।

प्रसंग:

- ओरान नोल्सन विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें मिर्गी के दौरों पर नियंत्रण पाने के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है।
- डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) डिवाइस, जो मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजती है, ने नॉलसन के दिन के समय होने वाले दौरों को 80% तक कम कर दिया है।

मिरगी

- मिर्गी, एक ऐसी स्थिति है जो बार-बार दौरे का कारण बनती है, जिसमें व्यक्ति को हाथ-पैरों में झटके, अस्थायी भ्रम, एकटक देखने की इच्छा या मांसपेशियों में अकड़न का सामना होता है।
- यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है।
- लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता। हालाँकि, सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिन्जाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि आनुवंशिकी भी मिर्गी का कारण बन सकती है।
- वर्ष 2022 के लैंसेट अध्ययन में की गई टिप्पणी के अनुसार, भारत में प्रति 1,000 लोगों में से 3 से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं।

यह डिवाइस कैसे काम करता है?

- न्यूरोस्टिम्यूलेटर असामान्य दौरे पैदा करने वाले संकेतों को बाधित या अवरुद्ध करने के लिए मस्तिष्क को लगातार विद्युत आवेग प्रदान करता है।
- डिवाइस DBS का उपयोग करता है, जिसका उपयोग पार्किंसंस और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े आंदोलन विकारों के लिए भी किया जाता है।
- हालाँकि बचपन में मिर्गी के लिए DBS का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक न्यूरोस्टिम्यूलेटर को छाती में (मस्तिष्क के बजाय) रखा जाता था, जिसमें तार मस्तिष्क तक जाते थे जहाँ प्रभावित क्षेत्र पर लीड लगाए जाते थे
- यह मिर्गी के इलाज की पहली पंक्ति नहीं है। डॉक्टर पहले एंटी-सीज़र दवाएँ और कीटोजेनिक आहार का उपयोग करते हैं, जिसमें वसा अधिक और कार्बोहाइड्रेट कम होता है।
- यद्यपि इसके कारणों को अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन कीटोजेनिक आहार से दौरे कम होने की बात ज्ञात है, यहां तक कि उपचार-प्रतिरोधी मिर्गी वाले बच्चों में भी।
- यदि यह उपाय काम न करे तो डॉक्टर मस्तिष्क की सर्जरी करके मस्तिष्क के उस हिस्से को हटा सकते हैं जहां से दौरे शुरू होते हैं।

DBS कितना महंगा है?

- न्यूरोस्टिम्यूलेटर की कीमत करीब 12 लाख रुपये है। निजी अस्पतालों में सर्जरी का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है
- इसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपकरणों का सुझाव केवल उन लोगों के लिए दिया जाना चाहिए जिनमें मिर्गी का दौरा पड़ता है और जिसकी उत्पत्ति मस्तिष्क के विभिन्न भागों (एक केंद्र बिंदु के बजाय) से होती है, जिससे ऑपरेशन कम व्यवहार्य हो जाता है।
- DBS भी एक विकल्प हो सकता है जब दवाएं और आहार दौरे को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं।

फैक्ट फटाफट

1. प्रोजेक्ट 75I

- प्रोजेक्ट 75I (प्रोजेक्ट 75 का अनुवर्ती) AIP तकनीक के डिजाइन और तकनीक के साथ-साथ इसके पूर्ववर्ती की अन्य विशेषताओं में सुधार है।
- AIP तकनीक के साथ, पनडुब्बियाँ ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं जो उन्हें दो सप्ताह तक पानी में रहने में सक्षम बनाती हैं।
- पहली पनडुब्बी में न्यूनतम 45% स्वदेशीकरण होना चाहिए, तथा छठी पनडुब्बी में स्वदेशीकरण की मात्रा 60% तक होनी चाहिए।
- यह परियोजना न केवल मुख्य पनडुब्बी निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगी, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से MSME के लिए, को भी बढ़ावा देगी।
- प्रोजेक्ट 75 (I) के अंतर्गत आने वाली पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आने वाली पनडुब्बियों से बड़ी हो सकती हैं।

2. सी-डैक

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सर्वोच्च अनुसंधान और विकास विंग है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना था।
- इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा सुपर कम्प्यूटरों के आयात से इनकार करने के परिप्रेक्ष्य में सुपर कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए की गई थी।
- सी-डैक ने 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपरकंप्यूटर परम 8000 बनाया।

3. व्यायाम मैत्री

- भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी (RTA) 16-29 सितंबर, 2019 तक मेघालय में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-2019 आयोजित करेंगे।
- अभ्यास मैत्री एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2006 से भारत और थाईलैंड में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- वैश्विक आतंकवाद के बदलते स्वरूप की पृष्ठभूमि में यह अभ्यास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आतंकवाद से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- थाईलैंड के दक्षिणी क्षेत्र (जैसे सतुन शहर, पथलुंग प्रांत, बैंकॉक आदि) जहां अधिकतर विदेशी आते हैं, आतंकवादी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं।
- इस अभ्यास का दायरा जंगलों और शहरी परिदृश्यों में उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर कंपनी स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है।

4. मार्स ओडिसी

- यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का प्रारंभिक मिशन था।
- इसे 7 अप्रैल 2001 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया था।
- ओडिसी अंतरिक्ष यान 2001 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है।
- ओडिसी का मूल लक्ष्य जल के संकेतों की खोज करना, ग्रह की सतह की सामग्रियों के विस्तृत मानचित्र बनाना और मनुष्यों के लिए विकिरण स्तर निर्धारित करना था।

- इस अंतरिक्ष यान के पास पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह की कक्षा में सबसे लंबे समय तक लगातार सक्रिय रहने का रिकॉर्ड है। इसका मिशन वर्ष 2025 तक चलने वाला है।
- इसने मंगल ग्रह की सतह को बनाने वाले रासायनिक तत्वों और खनिजों का पहला वैश्विक मानचित्र तैयार किया।

5. प्रोजेक्ट नेक्सस

- यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
- FPS ऑपरेटरों को प्रत्येक देश के लिए अनेक कस्टम कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता के स्थान पर, नेक्सस (Nexus) एक मानकीकृत, एकल-कनेक्शन समाधान प्रदान करता है, जो सीमाओं के पार निर्बाध लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- नेक्सस के साथ, एक FPS ऑपरेटर एकल नेटवर्क से जुड़ सकता है, जिससे नेटवर्क के भीतर अन्य देशों तक तुरंत पहुंच संभव हो सकेगी।
- इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के FPS को जोड़ना है; तथा भारत, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।
- इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों तक विस्तारित किया जा सकता है और इसके वर्ष 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है।

GEO IAS It's about quality

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यवस्था है जिसके तहत वे साझेदार देशों से बड़े मूल्य के आयात पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
2. FTA में सामान्यतः वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है, लेकिन IPR, निवेश आदि जैसे अन्य पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

Q2. भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में जनगणना हर 10 साल में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है
2. भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1871 में आयोजित की गई थी।
3. जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आवंटन के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q3. एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UPI भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है।
2. UPI उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन से कई बैंक खातों को जोड़ने की अनुमति देता है।
3. UPI पर लेनदेन की सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q4. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुई थी।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 स्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं।
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2
C. केवल 1 और 2
D. 1, 2 और 3

Q5. भारत में दालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है।
2. भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलों में चना, अरहर और काले चने शामिल हैं।
3. दालें भारतीय आहार में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और अपने नाइट्रोजन-फिक्सिंग गुणों के कारण मिट्टी की उर्वरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q6. निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें

1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
2. पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य
3. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व

उपर्युक्त में से कितने कावेरी बेसिन में स्थित हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q7. भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना है।
3. वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q8. गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गिनी गुणांक किसी देश के भीतर आय असमानता का माप है।
2. 0 का गिनी गुणांक पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 1 का गिनी गुणांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।
3. गिनी गुणांक का उपयोग केवल आय असमानता को मापने के लिए किया जा सकता है, धन असमानता को मापने के लिए नहीं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q9. भारत में शुष्क भूमि खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है।
2. इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार जैसी कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं।
3. इन क्षेत्रों में बाढ़ और मृदा अपरदन का खतरा हो सकता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q10. मिर्गी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक ऐसी स्थिति है जो बार-बार दौरे का कारण बनती है
2. यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है।
3. लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प B सही है

व्याख्या

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
  - यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यवस्था है जिसके तहत वे साझेदार देशों से बड़े मूल्य के आयात पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
  - अतः कथन 1 सही है।
  - कवरेज: समझौते में अन्य बातों के अलावा सेवाएं, निवेश और आर्थिक सहयोग भी शामिल हो सकते हैं।
  - FTA में सामान्यतः वस्तुओं का व्यापार (जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं का व्यापार (जैसे बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) शामिल होता है।
  - FTA अन्य क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर कर सकता है।
  - अतः कथन 2 गलत है।

उत्तर : 2 विकल्प C सही है

व्याख्या :

- भारत में जनगणना वास्तव में गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा हर 10 साल में आयोजित की जाती है। **कथन 1 सही है।**
- भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1871 में नहीं बल्कि 1881 में हुई थी। **कथन 2 सही है।**
- जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आवंटन के लिए किया जाता है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 3 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- UPI को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा। **कथन 1 गलत है।**
- UPI उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन से कई बैंक खातों को जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे खातों का प्रबंधन आसान हो जाता है। **कथन 2 सही है।**
- NPCI UPI पर लेनदेन की सुविधा के लिए जिम्मेदार है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 4 विकल्प A सही है

व्याख्या :

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुई थी। **कथन 1 सही है।**
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। **कथन 2 गलत है।**
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 5 विकल्प D सही है

व्याख्या :

- भारत वास्तव में दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। **कथन 1 सही है।**
- भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में चना, अरहर और काले चने शामिल हैं। **कथन 2 सही है।**
- दालें भारतीय आहार में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और अपने नाइट्रोजन-फिक्सिंग गुणों के कारण मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 6 विकल्प B सही है

व्याख्या

- कावेरी बेसिन में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं:
- नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान: नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। **इसलिए, कथन 1 सही है।**
- सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के इरोड जिले में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के बीच स्थित है। **इसलिए, कथन 2 सही है।**
- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम में मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। **इसलिए, कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 7 विकल्प A सही है

व्याख्या :

- वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। **कथन 1 सही है।**

- वित्त आयोग का एक प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना है। **कथन 2 सही है।**
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 8 विकल्प A सही है.

व्याख्या :

- गिनी गुणांक वास्तव में किसी देश के भीतर आय असमानता का एक माप है। **कथन 1 सही है।**
- 0 का गिनी गुणांक पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 1 का गिनी गुणांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है। **कथन 2 सही है।**
- गिनी गुणांक का उपयोग आय असमानता और धन असमानता दोनों को मापने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल आय असमानता को। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 9 विकल्प B सही है

व्याख्या

- फसल के मौसम के दौरान मिट्टी की नमी की पर्याप्तता के आधार पर वर्षा आधारित खेती को शुष्क भूमि और आर्द्रभूमि खेती में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में, शुष्क भूमि खेती बड़े पैमाने पर 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। **इसलिए, कथन 1 सही है।**
- इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार (चारा फसलें) जैसी कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं और मिट्टी की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। **इसलिए, कथन 2 सही है।**
- वेटलैंड खेती में, वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा हो सकता है। **इसलिए, कथन 3 गलत है।**
- इन क्षेत्रों में चावल, जूट और गन्ना जैसी विभिन्न जल-गहन फसलें उगाई जाती हैं तथा मीठे जल निकायों में जलीय कृषि की जाती है।

उत्तर : 10 विकल्प D सही है

व्याख्या

- मिर्गी, एक ऐसी स्थिति है जो बार-बार दौरे का कारण बनती है, जिसमें व्यक्ति को हाथ और पैर में झटके, अस्थायी भ्रम, घूरने के दौर या मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है।
- यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है।
- लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है। हालाँकि, सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिन्जाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि आनुवंशिकी भी मिर्गी का कारण बन सकती है।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com